



तमिलनाडु के उदय के तहत आने के बाद कुल 90 प्रतिशत से अधिक डिस्कॉम ऋण वाले राज्यों को उदय के तहत लाया जाएगा: श्री पीयूष गोयल 'उदय' वेब पोर्टल और मोबाइल एप्लिकेशन की शुरुआत

उदय क्लब में 20 राज्य शामिल हुए, असम और तेलंगाना ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

तेलंगाना को 6116 करोड़ रुपए और असम को कुल मिलाकर लगभग 1663 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हुआ

Posted On: 04 JAN 2017 6:34PM by PIB Delhi

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा और खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री पीयूष गोयल ने आज उज्जल डिस्कॉम एश्युरेंस योजना (उदय) वेब पोर्टल एंड मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। यह उदय योजना के तहत परिचालन और वित्तीय मानकों पर डिस्कॉम कंपनियों की प्रगति की निगरानी करेगा। 'डिजिटल इंडिया पहल' का एक महत्वपूर्ण भाग पोर्टल ऐप पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा और विभिन्न हितधारकों की जवाबदेही बढ़ाएगा और इसके अलावा उनके लिए बेहतर सेवाओं की मांग और उपभोक्ताओं को अपने लिए बेहतर सेवाओं की मांग करने में समर्थ बनाने के साथ-साथ वास्तविक प्रगति जानने में भी मदद करेगा।

उदय पोर्टल ऐप का ब्यौरा देते हुए श्री गोयल ने बताया कि यह विभिन्न डिस्कॉम द्वारा पिछले महीने/तिमाही में की गई नवीनतम प्रगति का विवरण उपलब्ध कराएगा। डिस्कॉम लेवल डाटा को राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर में एकीकृत किया जाएगा, जो प्रोसेस के बाद उन्नत कार्य निष्पादन विश्लेषण में प्रयुक्त किया जाएगा। राष्ट्रीय, राज्य और डिस्कॉम स्तर डैशबोर्ड इस प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र में नवीनतम वित्तीय और परिचालन प्रदर्शन की जानकारी उपलब्ध कराएंगे।

श्री गोयल ने कहा कि यह पोर्टल/ऐप विभिन्न राज्यों द्वारा हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापन की तार्किक अनुवर्ती कार्यवाही है, जो न केवल केन्द्रीय मंत्रालय स्तर पर डिस्कॉम द्वारा की गई प्रगति की निगरानी करने में समर्थ बनाएगा, बल्कि डिस्कॉम के कार्य प्रदर्शन में सुधार के लिए भविष्य की योजनाओं को बनाने में भी सहायता करेगा। यह पहली बार होगा जब विभिन्न विद्युत वितरण कंपनियों के कार्य प्रदर्शन का विवरण एक मंच पर ही उपलब्ध होगा, जिससे डिस्कॉम/राज्यों में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा। वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप की शुभारंभ के साथ पारदर्शिता और जवाबदेही की शुरुआत की प्रशंसा करते हुए श्री गोयल ने कहा की सार्वजनिक कार्यक्रमों और योजनाओं का कार्यान्वयन एक नागरिक प्रक्रिया बन गया है, क्योंकि इन पोर्टलों और ऐप में सभी जानकारी को जांच के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में रख दिया गया है।

राज्यों में उदय की उपलब्धियों का उदाहरण देते हुए उन्होंने राजस्थान डिस्कॉम का हवाला देते हुए बताया कि दो साल से भी कम अवधि में 15000 करोड़ रुपए की वार्षिक हानि जल्दी ही लाभ में बदल जाएगी। उन्होंने हरियाणा की प्रगति का भी उल्लेख किया, जहां एक उदाहरण के रूप में पंचकुला के 173 गांवों में 24 घंटे बिजली प्राप्त हो रही है। उन्होंने मंत्रालय के अधिकारियों को प्रोत्साहित करते हुए नवाचार रूप से सोचने और उदय के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाले राज्यों के लिए प्रदर्शन आधारित पुरस्कार के साथ आगे आने के लिए कहा। उन्होंने विभिन्न योजनाओं की जमीनी स्तर की उपलब्धियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए सिटीजन पोल शुरू करने के बारे में भी बातचीत की। आयोजन के दौरान तेलंगाना और असम अपने-अपने डिस्कॉम की वित्तीय और परिचालन प्रगति के लिए विद्युत मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करके उदय में शामिल हो गए हैं। इससे उदय क्लब में सदस्यों की संख्या 20 हो गई है। तमिलनाडु के बाद कुल 90 प्रतिशत से अधिक डिस्कॉम ऋण वाले राज्यों को उदय के तहत लाया जाएगा।

तेलंगाना सरकार कुल 11897 करोड़ रुपए के डिस्कॉम ऋण के 8923 करोड़ रुपए का अधिग्रहण करेगी, जबकि असम 1510 करोड़ रुपए के डिस्कॉम ऋण के 928 करोड़ रुपए का अधिग्रहण करेगी और बकाया ऋण को राज्य गारंटी वाले डिस्कॉम बांड के रूप में पुनः मूल्यांकित जारी किया जाएगा। इससे तेलंगाना और असम को ब्याज के रूप में क्रमशः 387 करोड़ और 37 करोड़ रुपए की वार्षिक बचत होगी। तेलंगाना को एटी एंड सी हानि और पारेषण हानियों में क्रमशः 9.95 प्रतिशत और 3 प्रतिशत की कटौती होने से 1476 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा, जबकि असम को लगभग 899 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। इन राज्यों को उदय में मांग पक्ष के प्रयासों के माध्यम से क्रमशः 1200 और 260 करोड़ रुपए का लाभ होने की उम्मीद है। इन राज्यों को विभिन्न कोयला सुधार प्रयासों के माध्यम से केन्द्र द्वारा दी जा रही सहायता के कारण क्रमशः 2250 करोड़ रुपए और 520 करोड़ रुपए का लाभ होने की भी उम्मीद है। तेलंगाना और असम को उदय के तहत क्रमशः 6116 करोड़ रुपए और 1663 करोड़ रुपए का कुल निवल लाभ भी प्राप्त होगा।

इस आयोजन में विद्युत सचिव, श्री पी. के. पुजारी, एमएनआरई सचिव, श्री राजीव कपूर, विशेष सचिव विद्युत और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आरईसी लिमिटेड, श्री बी.पी. पांडे, विशेष मुख्य सचिव ऊर्जा, तेलंगाना सरकार, श्री अजय मिश्रा, विद्युत सचिव, असम सरकार, जरीन रहमान अहमद और विद्युत मंत्रालय तथा मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के वरिष्ठ अधिकारी, उदय राज्यों के राज्य विद्युत सचिव भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए थे।

वीके/आईपीएस/डीके- 21

(Release ID: 1479967) Visitor Counter : 8

